खंड 6 अंक 1 अगस्त -2023
केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

बांध सुरक्षा और जल प्रबंधन के संबंध में हाल ही में किए गए विकास में हमारे प्रतिष्ठित संगठन द्वारा की गई पहल के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा करने में मुझे खुशी हो रही है। चूँकि हम अपने बांधों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की चुनौतियों से निपट रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण नियमों और सहयोगी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सूचित रहना और संलग्न रहना महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए) 2021 को लागू करना देश भर में निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 14 दिसंबर 2021 को अधिसूचित यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर 30 दिसंबर 2021 से लागू हो गया है। डीएसए के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे महीने में कई बैठकें बुलाई गईं, जिनमें डीआरआईपी-II योजना पर चर्चा भी शामिल थी।

हमारा संगठन, केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.), बांध सुरक्षा अधिनियम और डीआरआईपी पहल के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बांध की घटनाओं और विफलताओं पर स्थितिजन्य रिपोर्ट संकलित करने, माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को नियमित अपडेट प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। जिम्मेदारी के एहसास के साथ हम 18 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 की अवधि के दौरान पोंडी बांध, मध्य प्रदेश और मलाणा-II बांध, हिमाचल प्रदेश में दो बांध घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं।जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को संबोधित करने की हमारी प्रतिबद्धता में, जलवायु-स्मार्ट कृषि के लिए रास्ते तलाशने और कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाने के लिए कनाडाई प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की गई।

इसके अलावा, जर्मनी सरकार का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड), तकनीकी सहयोग परियोजना "गंगा कायाकल्प II (एसजीआर II) के समर्थन" पर जल शक्ति मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। "यूरोपीय संघ के समर्थन से सह-वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं पर जोर देते हुए भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आई ईडब्ल्यूपी) कार्रवाई को लागू करना है।

जल शक्ति मंत्रालय सक्रिय रूप से वृहत, मध्यम सिंचाई, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, परियोजनाओं के ईआरएम, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए निवेश मंजूरी प्रदान कर रहा है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागऔर जलशक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति की 18वीं बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से कुल 8 परियोजनाओं की सिफारिश की गई।

इसके अतिरिक्त, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर, जल शक्ति मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति ने सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर की अध्यक्षता में अपनी 152वीं बैठक में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार की सरकारों से कुल 12 परियोजनाओं/ योजनाओं को स्वीकार किया।

ये विकास बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने और व्यापक भलाई के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। मैं आपमें से प्रत्येक को इन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि साथ मिलकर हम अपने देश में जल संसाधनों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विषयसूची

एनडीएसए और डीआरआईपी

- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए)
- डीआरआईपी-II योजना और एनडीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा
- डीआरआईपी-II के तहत महाराष्ट्र के डिंभे बांध के रिसाव के उपचार के लिए उपयुक्त पद्धति अपनाने के मुद्दे को हल करने के लिए बैठक
- बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीएस)2023 के आयोजन के लिए संचालन समिति की पहली बैठक
- 100 से अधिक बांधों वाले राज्यों के साथ बैठक
- बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीएस) 2023 के आयोजन के लिए तकनीकी समिति
- डीआरआईपी चरण- II और III के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर बैठक
- बांध की घटनाओं/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

- संयुक्त राष्ट्र जल एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए), यूरोपीय संघ-भारत जल साझेदारी के भविष्य और कनाडाई प्रतिनिधिमंडल के साथ जल के भविष्य पर चर्चा
- यूरोपीय संघ के अध्ययन दौरे, रिबासिम और स्वाट पर प्रशिक्षण और आईसीआईडी कांग्रेस के समर्थन पर चर्चा के लिए जीआईजेड टीम के साथ बैठक

परियोजना के संबंध में बैठकें

- कनहर बांध परियोजना (उ.प्र.)
- किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाएँ
- रेओली दुगली जलविद्युत परियोजना, उत्तराखंड
- पोलावरम सिंचाई परियोजना
- उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना

प्रशिक्षण

- हिमालय में बदलती जलवायु के तहत ग्लेशियो-हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग

दौरा/निरीक्षण

- आईटीओ पर यमुना बैराज
- नानक सागर बांध, उत्तराखंड
- कनहर सिंचाई बांध परियोजना, उत्तर प्रदेश
- अपर तुंगा परियोजना, कर्नाटक
- गोसीखुर्द (मेजर-एनपी) सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र

अन्य गतिविधियाँ

- डीईए-एआईआईबी त्रिपक्षीय बैठक (नई दिल्ली)
- चर्चा के तहत वर्तमान मुद्दे सीडब्ल्यूएमए और रिलीज योजना व कावेरी बेसिन की स्थिति
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की चौथी बैठक

एनडीएसए और डीआरआईपी

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए)

श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 04.07.2023 को सेवा भवन, के.ज.आ. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न मुद्दों जैसे निदेशक और उससे नीचे के पद के भर्ती नियम (आरआर), आईआईटी रूड़की/ आईआईएससी बैंगलोर से बांध सुरक्षा के क्षेत्र में स्नातक करने वाले एम.टेक छात्रों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की पद्धति, और उनका पारिश्रमिक, आउटसोर्स पेशेवरों की नियुक्ति के लिए मानदंड /सलाहकार, एनडीएसए की वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति, एनडीएसए के लिए कार्यालय आवास के संबंध में मामला, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच डीओई द्वारा अनुमोदित पदों का वितरण, एनडीएसए में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन, गैर-आधिकारिक को बैठक शुल्क और टीए/डीए की पात्रता एनसीडीएस की दो उप-समितियों के सदस्य आदि पर चर्चा की गई।

डीआरआईपी-II योजना और एनडीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने डीआरआईपी-II योजना और एनडीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 17.07.2023 को डीओडब्ल्यूआर, एसएसबी के सम्मेलन कक्ष में सचिव, डीओडब्ल्यूआर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में चर्चा किए गए कुछ एजेंडा बिंदु थे-बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, बांध सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना, एनडीएसए के पदों का सृजन, धर्म पोर्टल का कार्यान्वयन आदि।

डीआरआईपी-II के तहत महाराष्ट्र के डिंभे बांध के रिसाव उपचार के लिए उपयुक्त पद्धति अपनाने के मुद्दे को हल करने के लिए बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में के.ज.आ., महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी और विश्व बैंक के अधिकारियों के बीच 18.07.2023 को डीआरआईपीआई के तहत डिंभे बांध, महाराष्ट्र के रिसाव उपचार के लिए उपयुक्त पद्धति अपनाने के मुद्दे को सुलझाने के लिए के.ज.आ., सेवा भवन, नई दिल्ली में सदस्य (डी एंड आर) के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी।

डिंभे बांध, जिसे महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी द्वारा डीआरआईपी-II के तहत पुनर्वासित करने का प्रस्ताव है, भारी रिसाव की समस्या का सामना कर रहा है। विश्व बैंक ने भारी रिसाव को नियंत्रित करने के लिए बांध के ऊपरी हिस्से पर जियोमेम्ब्रेन स्थापित करने की सिफारिश की है। हालाँकि, डीएसआरपी और परियोजना प्राधिकारियों की राय तकनीकी-आर्थिक समाधान के रूप में रिसाव को रोकने के लिए ग्राउटिंग करने की थी। सदस्य (डी एंड आर) जो अध्यक्ष (तकनीकी समिति-डीआरआईपी) भी हैं, ने निष्कर्ष निकाला कि महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी डिंभे परियोजना को डीआरआईपी से हटा सकता है, और महाराष्ट्र सरकार डिंभे के स्थान पर डीआरआईपी के तहत पुनर्वास के लिए किसी अन्य बांध का प्रस्ताव कर सकती है।

बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीएस) 2023 के आयोजन के लिए संचालन समिति की पहली बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीएस) 2023 के आयोजन के लिए संचालन समिति की पहली बैठक में भाग लिया, जो 21.07.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विशेष सचिव, जल संसाधन, आरडी एवं जीआर ने जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जलशक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, विश्व बैंक, डब्ल्यूएपीसीओएस, सीजीडब्ल्यूबी और राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया था। श्री विजयसरन, मुख्य अभियंता डीएसओ और परियोजना निदेशक, डीआरआईपी; एस.एस.बख्शी, निदेशक, डीएस ने सीपीएमयू, डीआरआईपी से बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, जयपुर में आईसीडीएस के आयोजन के लिए विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए, जिनमें सम्मेलन का स्थान, सम्मेलन के भागीदार, फंड की आवश्यकताएं, विभिन्न समितियों का गठन, वेबसाइट और पंजीकरण आदि शामिल हैं।

100 से अधिक बांधों वाले राज्यों के साथ बैठक

100 से अधिक बांध वाले राज्यों के साथ एनडीएसए के अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिब्बल की अध्यक्षता में 27.07.2023 को अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर) के कक्ष में हाइब्रिड मोड के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा किए गए एजेंडा बिंदु थे-

- राष्ट्रीय डेटाबेस की तैयारी और एनआरएलडी 2019 के अद्यतनीकरण के लिए निर्दिष्ट बांधों की सूची अद्यतन करना।
- प्री-मानसून निरीक्षण 2023-24 की स्थिति।
- बांधों के एसडीएसओ और ओएंडएम के लिए बजट प्रावधान।
- श्रेणी-II बाधों के निवारण हेतु योजना।
- बांधों की बांध सुरक्षा इकाइयों के तहत स्थापना की स्थिति।
- सभी बांधों की लॉग बुक के रखरखाव की स्थिति।

- ओएंडएम मैनुअल की स्थिति और क्या विशिष्ट बांधों के संबंध में ओएंडएम मैनुअल का पालन किया गया है या नहीं।
- जल विज्ञान, बांध की नींव और बांध की संरचनात्मक इंजीनियरिंग पर सभी तकनीकी दस्तावेजों की स्थिति
- वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति, और आपातकालीन कार्य योजना।

बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन(आईसीडीएस)2023 के आयोजन के लिए तकनीकी समिति

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) और अध्यक्ष, एनडीएसए ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीएस) 2023 के आयोजन के लिए तकनीकी समिति की पहली बैठक में भाग लिया। बैठक के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में 28.07.2023 को के.ज.आ. में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। श्री विजय सरन, परियोजना निदेशक (डीआरआईपी), श्री एस.डी. शर्मा, सीई डिज़ाइन (ई एंड एनई), श्री अनिल जैन, सीई डिज़ाइन(एनडब्ल्यू एंड एस)और एनडीएसए/ डीआरआईपी/के.ज.आ. के अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। विश्व बैंक, आईआईटी रूड़की, एमएनआईटी जयपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के शेड्यूल, उसके सम्मेलन, प्रत्येक तकनीकी सत्र के लिए अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष, ब्रोशर और वेबसाइट आदि सहित विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है और उस पर निर्णय लिया गया है।

डीआरआईपी चरण- II और III के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर बैठक

मुख्य अभियंता (एसपीएमयू-डीआरआईपी, आंध्र प्रदेश डब्ल्यूआरडी), परियोजना निदेशक (एसपीएमयूडीआरआईपी, आंध्र प्रदेश डब्ल्यूआरडी) और कार्यकारी अभियंता (एसपीएमयू-डीआरआईपी, आंध्र प्रदेश डब्ल्यूआरडी) ने 12.07.2023 को सीपीएमयू-के.ज.आ. का दौरा किया। एसपीएमयू-डीआरआईपी, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डीएसओ और श्री समीर कुमार शुक्ला (निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय, के.ज.आ.)से मुलाकात की। बैठक के दौरान, डीआरआईपी चरण- II और III के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बांध घटनाओं/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट

के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई बांध घटना/ विफलता पर स्थितिजन्य रिपोर्ट नियमित रूप से संकलित की जा रही है और माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 18.07.2023 से 31.07.2023 की अवधि की स्थितिजन्य रिपोर्ट माननीय जलशक्ति मंत्रालय के कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गई है।18.07.2023 से 31.07.2023 की अवधि

के दौरान परियोजना अधिकारियों और एनडीएसए द्वारा पोंडी बांध, मध्य प्रदेश और मलाणा-द्वितीय बांध, हिमाचल प्रदेश में दो बांध की घटनाओं की सूचना दी गई है। इन बांध घटनाओं के संबंध में प्राप्त विवरण इस प्रकार हैं:-

ए. पोंडी जैतगढ़ बांध, जिला दमोह, मध्य प्रदेश

परियोजना अधिकारियों ने बताया कि 23.07.2023 से 24.07.2023 के बीच भारी बारिश के कारण, जलाशय में पानी अचानक एफटीएल तक पहुंच गया था और शिखर के ऊपर से लगभग एक फुट जल स्तम्भ के साथ अपशिष्ट मेड़ से बाहर निकल गया था। 24.07.2023 की शाम 6.00 बजे किसानों द्वारा बांध से रिसाव (नहर स्लुइस निर्गम के पास बोल्डर पदाग्र के ठीक नीचे) की सूचना दी गई। कार्यकारी अभियंता ने अपनी टीम के साथ प्रतिलोमित निस्यंदक(उल्टे फिल्टर) का निर्माण करके मिट्टी के रिसाव या कटाव को रोकने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए क्योंकि रिसाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बांध की निचली धारा में भारी रिसाव और मिट्टी के खिसकने को देखते हुए, कार्यपालन अभियंता ने तुरंत कलेक्टर, दमोह को भारी बाढ़ के साथ बांध टूटनेकी संभावना व्यक्त की, जिन्होंने तुरंत ग्रामीणों को हटाने के निर्देश दिए। सौभाग्य से, 24.07.2023 की रात में दोनों निचले गांवों को खाली करा के ग्रामीणों को हटा लिया गया। 25.07.2023 की सुबह 5:00 बजे आरडी 220 से 270 मीटर के बीच बांध टूट गया। किसी भी मानव और पशु हानि की सूचना नहीं है। बांध सुरक्षा, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने 26.07.2023 को बांध का निरीक्षण किया।

बी. मलाणा-II एचईपी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने सभी त्रिज्य कपाटों (रेडियल गेटों) के जाम होने के कारण मलाणा खड्ड पर मलाणा-द्वितीय बांध के उपरिप्लाव के मामले पर राज्य बांध सुरक्षा समिति(एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन(एसडीएसओ), हिमाचल प्रदेश को संबोधित किया और स्थिति रिपोर्ट/विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

राज्य बांध सुरक्षा संगठन(एसडीएसओ), हिमाचल प्रदेश ने बताया कि मलाणा-II बांध उपरिप्लाव पर था क्योंकि दोनों त्रिज्य कपाट कीचड़ और बोल्डर के कारण जाम हो गए थे, जैसा कि बांध अधिकारियों ने बताया था। पानी बांध के ऊपर से बह रहा था और बाएं किनारे पर कटाव हो गई थी, जिससे बांध तक पहुंचने का रास्ता खत्म हो गया था। यदि डिस्चार्ज बढ़ता है तो बांध टूटने की संभावना हो सकती है।

ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 29.07.2023 को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि मलाणा-द्वितीय बांध पर मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप अभी तक गेट नहीं खोले गए हैं। स्थिति की जांच करने और बाधाओं एवं अन्य पहलुओं को देखते हुए अन्य सभी संभावनाओं का ऑन-साइट मूल्यांकन करने हेतु 30 जुलाई 2023 को बांध स्थल का दौरा करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कदम जलाशय, तेलंगाना में ऊपरी धारा से भारी प्रवाह हुआ और जल स्तर 700 फीट के स्तर तक पहुंच गया और 7 टीएमसी पानी की पूरी क्षमता को छू गया। कदम सिंचाई परियोजना के 18 में से चार गेट जाम हो गए और 21.07.2023 को अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इसे उठाया नहीं जा सका। बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) की एक तकनीकी टीम ने 28.07.2023 को बांध स्थल का निरीक्षण किया। कार्यालय सदस्य (आपदा एवं लचीलापन) एनडीएसए ने परियोजना अधिकारियों से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

संयुक्त राष्ट्र जल एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए), यूरोपीय संघ-भारत जल साझेदारी के भविष्य और कनाडाई प्रतिनिधिमंडल के साथ जल के भविष्य पर चर्चा

बैठक में जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बीच बढ़ते संबंध, जलवायु-स्मार्ट कृषि/कम पानी वाली फसलों की ओर बदलाव, मौजूदा या नए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के माध्यम से भारतीय राज्यों को आईईडब्ल्यूपी /आईईडब्ल्यूआई के भीतर लाने की आवश्यकता, शहरी जल विज्ञान और जल क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा हुई।

यूरोपीय संघ के अध्ययन दौरे, रिबासिम और स्वाट पर प्रशिक्षण और आईसीआईडी कांग्रेस के समर्थन पर चर्चा के लिए जीआईजेड टीम के साथ बैठक

जर्मनी सरकार का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) तकनीकी सहयोग परियोजना "गंगा कायाकल्प II (एसजीआर II) को समर्थन" पर जल शक्ति मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। यूरोपीय संघ के साथ सह-वित्त पोषित परियोजना का एक घटक भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी(आईईडब्ल्यूपी) कार्रवाई के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

एसजीआर II के एक भाग के रूप में, बेल्जियम और नीदरलैंड के

लिए एक अध्ययन यात्रा आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि भारतीय प्रतिनिधियों को शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की व्यापक समझ से लैस किया जा सके। अंततः, यह अनुभव भारतीय शहरों के लिए एक बेहतर प्रबंधन रणनीति के विकास में सहायता करेगा, जिससे अधिक लचीला और प्रभावी शहरी बाढ़ प्रबंधन हो सकेगा।

इसके अलावा, नदी बेसिन सिमुलेशन मॉडल (आर आईबीएएसआईएम) और एसडब्ल्यूएटी में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के भारतीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

केंद्रीय जल आयोग ने विशाखापत्तनम (विजाग), आंध्र प्रदेश, भारत में आगामी 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस और 74वीं आईईसी बैठक (नवंबर 02,2023-नवंबर 08,2023) में भाग लेने और योगदान देने के लिए आईईडब्ल्यूपी एक्शन को आमंत्रित किया। आईईडब्ल्यूपी एक्शन ने आईईडब्ल्यूपी एक्शन प्लान और कांग्रेस के दायरे दोनों से संबंधित विषयों पर आदान-प्रदान करने के लिए यूरोपीय विशेषज्ञता और अनुभवों को लाकर कांग्रेस की विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित करने और समर्थन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। आईईडब्ल्यूपी ने कांग्रेस के युवा-व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यूरोप से युवा पेशेवरों को आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव रखा।
इसके अलावा, आईईडब्ल्यूपी एक्शन कांग्रेस के दौरान आईईडब्ल्यूपी एक्शन की गतिविधियों, सफलता की कहानियों और सीख को प्रस्तुत करने के लिए साथ में एक पार्श्व कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

जीआईजेड टीम के साथ अध्यक्ष (के.ज.आ.) की बैठक में उपरोक्त अध्ययन दौरे, रिबासिम और स्वाट पर प्रशिक्षण; और आईसीआईडी कांग्रेस को समर्थन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

परियोजना के संबंध में बैठकें

कनहर बांध परियोजना(उ.प्र.)

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने कनहर बांध परियोजना (यूपी) से संबंधित मुद्दों विशेष रूप से बांध के दोनों किनारों पर मिट्टी की चोटियों पर विकसित दरारों के बारे में पर चर्चा करने के लिए 18.07.2023 को 11:15 बजे केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित बैठक में भाग लिया।

श्री विवेक त्रिपाठी, सीई डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) और श्री सोमेश कुमार, निदेशक, तटबंध (एन एंड डब्ल्यू) के.ज.आ. से और डब्ल्यूआरडी, यूपी सरकार के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में संपूर्ण कनहर बांध के लिए प्रदान किए गए मुफ्त बोर्ड की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए तटबंध (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय, के.ज.आ. में फ्रीबोर्ड अध्ययन करना, परियोजना अधिकारियों द्वारा बाएँ और दाएँ दोनों किनारों पर मृदाबांध के शिखर पर दरारों की सीमा और पैटर्न की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त और अनुभवी एजेंसी के माध्यम से एक भूभौतिकीय सर्वेक्षण/जांच कराना, बाढ़ की परिस्थितियों के दौरान स्पिलवे के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने की स्थिति में प्रभावित होने वाली आबादी का आकलन करने के लिए बांध के बहाव क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) तैयार करना आदि शामिल है।

बैठक में कनहर बांध के निरीक्षण के लिए के.ज.आ., सीएसएमआरएस के अधिकारियों और कनहर बांध परियोजना के डिजाइनरों और राज्य एसडीएसओ की एक विशेषज्ञ टीम बनाने और बांध की समग्र स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाएँ

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 01.07.2023 को किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के चल रहे आईडब्ल्यूटी मुद्दों के संबंध में स्मारक अध्याय (अध्याय-V-डिज़ाइन) को अंतिम रूप देने के लिए के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया। इसी संबंध में के.ज.आ. में 10.07.2023, 11.07.2023, 13.07.2023 और 14.07.2023 को लगातार बैठकें आयोजित की गईं।

रेओली दुगली जलविद्युत परियोजना, उत्तराखंड

रेओली डुगली जलविद्युत परियोजना में प्रस्तावित सर्ज शाफ्ट के असामान्य रूप से बड़े व्यास की समस्या है जो 43.8 मीटर व्यास वाले गुंबद के साथ 39.5 मीटर है जो निष्पादन के दौरान स्थिरता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है। इतने बड़े भूमिगत प्रोत्कर्ष कूपक (सर्ज शाफ्ट) उपलब्ध कराने का कोई उदाहरण नहीं है और संरचना की सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए के.ज.आ. इतने बड़े आकार के प्रोत्कर्ष कूपक (सर्ज शाफ्ट) के पक्ष में नहीं है। परियोजना प्राधिकरण को ट्विन एचआरटी के साथ ट्विन प्रोत्कर्ष कूपक (सर्ज शाफ्ट) का विकल्प और अभिन्यास को संशोधित करके खुले प्रोत्कर्ष कूपक(ओपन सर्ज शाफ्ट) के विकल्प का सुझाव दिया गया। अब, एसजेवीएन ने ट्विन प्रोत्कर्ष कूपक (सर्ज शाफ्ट) के साथ ट्विन हेड रेस सुरंग (एचआरटी) सहित रेओली डुगली जलविद्युत परियोजना के अभिन्यास की परिकल्पना की है। अभिन्यास पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ. और एसजेवीएनएल के अधिकारियों के बीच 27.07.2023 को केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी।

पोलावरम सिंचाई परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने पोलावरम सिंचाई परियोजना की स्थिति की समीक्षा के लिए 03.07.2023 को आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने की।

इसके अलावा, पोलावरम सिंचाई परियोजना के ईसीआरएफ बांध की डायाफ्राम दीवार (डी-दीवार) के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 10.07.2023 को भौतिक मोड में एक और बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की विशेष सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने की और बैठक पीआईपी के प्रमुख तकनीकी और डिजाइन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की गई। श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने बैठक में भाग लिया।

इसके अलावा, 24.07.2023 को आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना में अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध की स्थिति की समीक्षा करने के लिए के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) और केंद्रीय जल आयोग, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), सीएसएमआरएस, डब्ल्यूएपीसीओएस और पोलावरम सिंचाई परियोजना के डिजाइन और निर्माण में शामिल अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जल स्तर की वर्तमान स्थिति, अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध में रिसाव, मानसून के मौसम के दौरान कार्य क्षेत्र तक पहुंच और आगे की राह पर विचार-विमर्श किया गया।

बांध डिजाइन समीक्षा पैनल की 22वीं बैठक:

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 30 जुलाई 2023 को आयोजित पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के बांध डिजाइन समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) की बाईसवीं बैठक में

भाग लिया। डीडीआरपी के अध्यक्ष श्री ए.बी.पांड्या ने वीसी के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की और पीपीए, के.ज.आ., डब्ल्यूआरडी-जीओएपी, सीएसएमआरएस, एनएचपीसी, कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारियों और डब्ल्यूआरडी के सलाहकारों के साथ पैनल के अन्य सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य डी एंड आर ने बैठक में चर्चा की जाने वाली कार्यसूची मदों पर पैनल के सदस्यों को विस्तार से बताया। मुख्य बांध के गड्ढे क्षेत्र में रिसाव का मुद्दा और गैप-II ईसीआरएफ बांध में डी-दीवार निर्माण। बैठक में निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूआरडी विधिवत समावेश कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

ए. एचपीटी परीक्षण और उपलब्ध दाबमापी/पीज़ोमीटर डेटा द्वारा अनुमानित पारगम्यता मूल्यों का उपयोग करके यूएससीडी के प्रतिप्रवाह में मृत्तिका आवरण से रिसनरोक(कट-ऑफ) के साथ और बिना रिसनरोक के रिसाव विश्लेषण।

बी. यूएससीडी के लिए संभावित उपचारात्मक उपाय, जिसमें एक विशेषज्ञ एजेंसी से परामर्श के बाद उनकी कार्यान्वयन रणनीति और प्रभावकारिता शामिल है।

सी. बांध के गड्ढे क्षेत्र से पानी के ह्रास के लिए विस्तृत प्रस्ताव, जिसमें उनकी सुदृढ़ता पर तकनीकी विवरण भी शामिल है।

डी-वॉल सहित मुख्य बांध के निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध मौसम, श्रमिक और सामग्री की उपलब्धता पर विधिवत विचार करते हुए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों के संबंध में कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 13.07.2023 को और उसके बाद 27.07.2023 को एक बैठक ली गई थी।

कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति, परियोजना की सिंचाई योजना, WAPCOS द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, एक बार हेतु आर एंड आर पैकेज, शेष कार्य के लिए कार्य योजना, परियोजना के लिए सीए रिलीज और इसके उपयोग आदि जैसे परियोजना के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में एफएम विंग डीओडब्ल्यूआर, के.ज.आ. मुख्यालय, डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए 25.07.2023 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक और बैठक ली गई। बैठक के दौरान, माननीय मंत्री ने तत्काल आधार पर निम्नलिखित कार्य करने का निर्देश दिया:

(1) के.ज.आ. और डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों को तुरंत परियोजना स्थल का दौरा करना चाहिए और झारखंड में दाहिनी मुख्य नहर (आरएमसी) में किए गए कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण पहलू के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

(2) के.ज.आ. द्वारा परियोजना की गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित पहलुओं सहित नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए (इस संबंध में उप-समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं)।

(3) डब्ल्यूएपीसीओएस को फरवरी 2024 तक डीएएम साइट पर गेट्स की स्थापना के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए क्योंकि परियोजना के शेष कार्य के लिए कैबिनेट नोट की मंजूरी अग्रिम चरण में है।

प्रशिक्षण

हिमालय में बदलती जलवायु के तहत हिमनद जलविज्ञान (ग्लेशियो-हाइड्रोलॉजिकल) मॉडलिंग

स्विस विकास और सहयोग एजेंसी (एसडीसी) ने केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के सहयोग से 3 जुलाई से 7 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली में "हिमालय में बदलती जलवायु के तहत ग्लेशियो-हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य हिमालय में हिमनदों के पिघलने की बढ़ती दर के प्रभावों का आकलन करना था, जो कि गंभीर चुनौतियाँ पैदा करता है। स्वागत भाषण के दौरान, अध्यक्ष (के.ज.आ.) और भारत सरकार के पदेन सचिव ने कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग सहित सभी क्षेत्रों में मीठे पानी की बढ़ती मांग पर जोर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए, निर्णय निर्माताओं के लिए हिमालयी क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन से प्रेरित परिवर्तनशीलता और पानी की उपलब्धता में अनिश्चितता का आकलन करना और इन चुनौतियों के मद्देनजर जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है।

दौरा/निरीक्षण

आईटीओ पर यमुना बैराज

के.ज.आ. के अधिकारियों द्वारा सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली के अधिकारियों के साथ 27.07.2023 को आईटीओ, नई दिल्ली में यमुना बैराज का दौरा किया गया था। श्री शरद चंद्रा, निदेशक, एफएफएम निदेशालय, श्री सतीश कंबोज, निदेशक, गेट्स डिज़ाइन (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय, श्री समीर कुमार शुक्ला, निदेशक, बीसीडी (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय और श्रीघनश्याम पटेल, उप निदेशक, गेट्सडिज़ाइन (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय यात्रा के दौरान उपस्थित थे।

नानक सागर बांध, उत्तराखंड

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई प्रभाग, बरेली ने के.ज.आ. से नानक सागर बांध का निरीक्षण करने और नानक सागर जलाशय में रिसाव और बहाव के वर्तमान मुद्दों पर सुझाव देने का अनुरोध किया। बांध के डाउनस्ट्रीम में देखे गए रिसाव और बहाव के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए के.ज.आ. और सीएसएमआरएस के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा 13-14 जुलाई, 2023 को नानक सागर बांध, उत्तराखंड पर एक निरीक्षण दौरा किया गया था।

कनहर सिंचाई बांध परियोजना, उत्तर प्रदेश

श्री विवेक त्रिपाठी, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), श्री सोमेश कुमार, निदेशक, तटबंध (एन एंड डब्ल्यू) और श्री कमलेश जैन, उप निदेशक, तटबंध (एन एंड डब्ल्यू) ने बांध के मृदा वाले हिस्से के शीर्ष पर देखी गई दरारों से संबंधित तकनीकी मुद्दों के मद्देनजर सीएसएमआरएस और एसडीएसओ के अधिकारियों के साथ 27 से 29 जुलाई 2023 तक कनहर सिंचाई बांध परियोजना (यूपी) का दौरा किया।

अपर तुंग परियोजना, कर्नाटक

मुख्य अभियंता श्री वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एमएसओ, बेंगलुरु की एक निगरानी टीम के साथ डॉ. जे हर्ष, निदेशक और श्री प्रताप शेल्के, डीडी ने 17 से 19 जुलाई 2023 तक पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में पहली निगरानी यात्रा के रूप में ऊपरी तुंगा परियोजना, कर्नाटक का दौरा किया।

टीम ने परियोजना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जुलाई 2023 तक निष्पादित विभिन्न एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने काम पूरा होने में बाधा बन रहे अड़चन बिंदुओं का भी दौरा किया और परियोजना अधिकारियों को काम को शीघ्र और समयबद्ध पूरा करने की सलाह दी।

गोसीखुर्द (वृहत-राष्ट्रीय परियोजना)सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र

गोसीखुर्द (वृहत-राष्ट्रीय परियोजना) सिंचाई परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी वैनगंगा नदी पर किया गया है। इस परियोजना को 2008-09 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है। इस परियोजना की योजना 19000 हेक्टेयर सीए(250800 हेक्टेयर यूआईपी) क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने के लिए बनाई गई है। परियोजना के लिए रु.796.105 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

श्री नीरज कुमार मांगलिक, मुख्य अभियंता, एमसीओ, के.ज.आ., नागपुर ने निदेशक और उप निदेशक निगरानी निदेशालय, नागपुर के साथ पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत शामिल परियोजना घटकों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए 11.07.2023 से 12.07.2023 के दौरान परियोजना का दौरा किया।दौरे के दौरान मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द परियोजना और जल संसाधन विभाग के अधिकारी साथ थे।

के. ज. आ. की अन्य गतिविधियाँ

डीईए-एआईआईबी त्रिपक्षीय बैठक (नई दिल्ली)

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की 7वीं त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक (टीपीआरएम) 28.07.2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता डीएसओ और परियोजना निदेशक, डीआरआईपी, श्री एस.एस. बख्शी, निदेशक, डीएसआर और श्री सौरभ शरण, उप निदेशक, डीएसआर भी बैठक में शामिल हुए। परियोजना निदेशक, डीआरआईपी ने डीआरआईपी-2 से संबंधित प्रगति और मुद्दों के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। विश्व बैंक और एआईआईबी के बीच ऋण साझाकरण व्यवस्था का मामला उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था जिस पर विस्तार से चर्चा की गई।

चर्चा के तहत वर्तमान मुद्दे सीडब्ल्यूएमए व रिलीज योजना और कावेरी बेसिन की स्थिति

माननीय मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा 18.07.2023 को के.ज.आ., सीडब्ल्यूएम के अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने के.ज.आ. की ओर से बैठक में भाग लिया। बैठक में, कावेरी बेसिन में सभी जल-मौसम संबंधी स्थिति और कावेरी जल छोड़ने के संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सीडब्ल्यूएमए को नियमित अंतराल पर कावेरी बेसिन में जल-मौसम संबंधी स्थिति की समीक्षा करने और एक संकट साझाकरण फॉर्मूला विकसित करने का प्रयास करने के लिए कहा गया।

निवेश मंजूरी समिति की 18वीं बैठक

डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर और जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति की 18वीं बैठक सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस की अध्यक्षता में 10.07.2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ. और जीएफसीसी के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कुल 8 परियोजनाओं को निवेश मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया। परियोजनाओं का विवरण तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	श्रेणी	लागत (रुपये) करोड़ में और मूल्य स्तर	लाभ
1.	फीना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	बहुउद्देशीय परियोजना	643.68 करोड़ रुपये मार्च 2022 के मूल्य स्तर पर	सीसीए- 4025 हेक्टेयर बिजली - 1.88 मेगावाट
2.	ऊना जिले की तहसील अम्ब में ब्यास बेसिन से जुड़ने वाली स्वान नदी और उसकीसहायक नदियों के लिए बाढ़ सुरक्षा उपाय	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	अप्रैल, 2021 के मूल्य स्तर पर 339.25 करोड़ रुपये	क्षेत्र संरक्षित: 510.18 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या : 14744
3.	तहसील बिश्नाह और सुचेतागढ़ में ऐक नाला के बायीं और दायीं ओर, एनएच-1ए, पीएच.-I के डाउनस्ट्रीम पर गांव खीरी से साई के बीच विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कार्यों का निर्माण	जम्मू एवं कश्मीर	बाढ़ नियंत्रण	2020 के मूल्य स्तर पर 23.05 करोड़ रुपये	संरक्षित क्षेत्र: 140 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या: 1500
4.	मुर्शिदाबाद जिले की कुल 1,830.00 मी लंबाई में सीमा चौकी (बीओपी)एट्रोसिया और रेनू केउत्तरदायी क्षेत्र(एओआर) में पद्मा नदी के दाहिने किनारे पर कटाव-रोधी कार्य	पश्चिम बंगाल	बाढ़ नियंत्रण	2022 के मूल्य स्तर पर रु 73.83 करोड़	संरक्षित क्षेत्र: 2500 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या 35000
5.	कामले जिले में दोलुंगमुख क्षेत्र की कृषि भूमि और गांव की रक्षा के लिए दोलुंग नदी के दोनों किनारों पर कटावरोधी कार्य	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	मार्च 2021 के मूल्य स्तर पर रु.18.26 करोड़	संरक्षित क्षेत्र: 200 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या: 3500
6.	पक्के केसांग जिलों के सिजोसा में डेकोराई सिंचाई परियोजना के ऊपरी हिस्से में सामान्य जमीन के पास बाढ़ सुरक्षा कार्य	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	जनवरी, 2022 के मूल्य स्तर पर रु.82.16 करोड़	संरक्षित क्षेत्र: 550 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या: 12474
7.	टिहरी गढ़वाल में अगलाड नदी से थथ्यूर एवं भवन के लिए बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य हेतु परियोजना	उत्तराखंड	बाढ़ नियंत्रण	2021 के मूल्य स्तर पर रु 30.22 करोड़	संरक्षित क्षेत्र: 29.70 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या: 3750
8.	जनपद पौडी गढ़वाल के पूलचट्टी एवं रतनपानी गांवों की सुरक्षा हेतु हिनवाल नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षा योजना	उत्तराखंड	बाढ़ नियंत्रण	अक्टूबर 2022 के मूल्य स्तर पर 22.23 करोड़ रुपये	संरक्षित क्षेत्र: 103 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या: 8860

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की चौथी बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एंड डब्लूएम के पुन:अभिमुखीकरण के लिए कार्य समूह की चौथी बैठक सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) की अध्यक्षता में 28.07.2023 को आयोजित की गई थी।

इस बैठक में पोमियो, के.ज.आ.; पीएओ, के.ज.आ.; एनएमसीजी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर के सीएडीडब्ल्यूएम से इनपुट प्राप्त हो गये हैं। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न संगठनों/विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

सलाहकार समिति की 152वीं बैठक

सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 152वीं बैठक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 14.07.2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार सरकार के अलावा के.ज.आ., जीआरएमबी, सीजीडब्ल्यूबी, जीएफसीसी, एमओटीए, एमओईएफ और सीसी, सीईए, नीति आयोग, एमओएफ आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में सलाहकार समिति द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुल 12 (बारह) परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकार किया गया:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वर्ग	अनुमानित लागत	लाभ
1	नीरा देवघर सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद सिंचाई	जून, 2022 के स्तर पर 3591.46 करोड़ रुपये	सीसीए- 62706 बीसी अनुपात: 1.55
2	शाहपुर कंडी बांध परियोजना की तीसरी आर.सी.ई.	पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर	वृहद सिंचाई	3394.49 करोड़ रुपये (अक्टूबर 2022 के स्तर पर)	सीसीए- 37173 हेक्टेयर बीसी अनुपात: 1.65 पावर: 206 मेगावाट
3	कडेम-गुडेम उत्थापन सिंचाई योजना (परियोजना 2015 में पूरी हुई)	तेलंगाना	वृहद सिंचाई	रु. 138.45 करोड़ (मार्च 2015 के स्तर पर)	सीसीए-12,141 हेक्टेयर बीसी अनुपात:1.74
4	संजय सरोवर परियोजना जिला सिवनी एवं बालाघाट का विस्तार जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	मध्य प्रदेश	वृहद सिंचाई	मार्च 2023 के स्तर पर 332.54 करोड़ रुपये	सीसीए- 81,829 हेक्टेयर बीसी अनुपात : 1.56
5	मोदीकुंटावगु सिंचाई परियोजना	तेलंगाना	मध्यम सिंचाई	500.2553 करोड़ रुपये (2021-22 के स्तर पर)	सीसीए- 5500 हेक्टेयर बीसी अनुपात: 1.503
6	भौंरत बांध परियोजना का आर.सी.ई.	उत्तर प्रदेश	मध्यम सिंचाई	1252.12 करोड़ रुपये (मार्च, 2022 के स्तर पर)	सीसीए- 9850 हेक्टेयर बीसी अनुपात: 1.14
7	पचिन नदी पर डीपीएस ब्रिजपॉइंट रेची से इटानगर के तहत पगातारा तक कटाव रोधी कार्य	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	88.36 करोड़ रुपये (नवंबर 2022 के स्तर पर)	लाभान्वित जनसंख्या- लगभग 3000 व्यक्ति लाभान्वित क्षेत्र- लगभग 450 हे. ग्रामीण क्षेत्र बीसी अनुपात-1.41
8	पसीघाट उप-मंडल के अंतर्गत सिबोकोरोंग नदी पर कटाव नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	35.50 करोड़ रुपये (दिसंबर 2022 के स्तर पर)	लाभान्वित जनसंख्या- लगभग 12500 लाभान्वित क्षेत्र- लगभग 120 हे बीसी अनुपात-1.82
9	चंद्रनगर, ईटानगर में सेंकी नदी पर कटाव रोधी कार्य	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	73.21 करोड़ रुपये (नवंबर 2022 के स्तर पर)	लाभान्वित जनसंख्या- लगभग 18000. लाभान्वित क्षेत्र- लगभग 68 हेक्टेयर बीसी अनुपात-1.38
10	बाएं कमला बलान तटबंध(एलकेबीई) और दाएं कमला बलान तटबंध (आरकेबीई) चरण-I (पिपराघाट पुल से ठांगा पुल) एलकेबीई किमी 27.10 से किमी 66.30 के बीच और आरकेबीई किमी 23.20 से किमी 64.00 के बीच का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण।	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	325.1232 करोड़ रुपये (2019 के स्तर पर)	लाभान्वित जनसंख्या- 1200000. लाभान्वित क्षेत्र- 48000 हेक्टेयर बीसी अनुपात- 1.19
11	"बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध (द्वितीय चरण) को एलकेबीई के किमी 66.300 (फटकी कुट्टी) से किमी 92.500 (पुनाच) तक और आरकेबीई के किमी 64.00 (थेंगा) से किमी 94.00 (पलवा) तक ऊपर उठाना, मजबूत करना और पक्कीकरण करना	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	297.07 करोड़ रुपये (2022 के स्तर पर)	बीसी अनुपात : 1.98 लाभित जनसंख्या: 1200000 लाभित क्षेत्र : 72300 हेक्टेयर
12	आर्मी कैंप-2 बटालियन परिसर गलाती, धारचूला ब्लॉक, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में काली नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	उत्तराखंड	बाढ़ नियंत्रण	रु. 40.601 करोड़ (अक्टूबर, 2022 के स्तर पर)	बीसी अनुपात : 1.45 लाभान्वित जनसंख्या : 600 लाभान्वित क्षेत्र : 14.0 हेक्टेयर

31.07.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान (2023-24)	व्यय	व्यय (%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	162.130	43.9259	27.09%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	20.000	3.827	1.91%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	20.310	3.321	16.35%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.000	1.5376	13.98%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.58	1.9644	6.22%

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस और 74वीं आईईसी बैठक के आयोजन के लिए आयोजन समिति की चौथी बैठक

आयोजन समिति की चौथी बैठक 25.07.2023 को हाइब्रिड मोड में श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी और आईएनसीआईडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें आईसीआईडीई कार्यक्रमों की तैयारियों, संचार के समानांतर चैनलों की व्यापकता, आगे की राह और अन्य मुद्दों के संबंध में प्रगति पर चर्चा की गई थी। समिति ने प्रदर्शनी और स्थल को अंतिम रूप देने, कार्यक्रम, प्रायोजन व्यवस्था, वित्तीय मामलों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

देश में बाढ़ की स्थिति-जुलाई 2023

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 31 जुलाई 2023 की अवधि के दौरान, कुल2382 (1779 स्तर+603 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमानजारी किएगए, और 2207 (1642 स्तर+565 प्रवाह) पूर्वानुमान 92.65 % प्रतिशतसटीकता केसाथ अनुमेयसीमा केभीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 31 जुलाई 135 रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) और 129 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए थे।

01.05.2023 से 31.07.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में चरम बाढ़ की स्थिति

04 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र.सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	एनसीटी दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	यमुना	दिल्लीरेलवे ब्रिज	12/07/2023 13	15/07/2023 09
2	उत्तर प्रदेश	बदायूँ	गंगा	कछलाब्रिज	14/07/2023 22 16/07/2023 11 29/07/2023 18	15/07/2023 18 22/07/2023 04 31/08/2023 23
3	असम	शिवसागर	दिखोव	शिवसागर	17/07/2023 05	17/07/2023 13
4	तेलंगाना	कुमुराम भीम	वर्धा	सिरपुर नगर	24/07/2023 13 29/07/2023 05	24/07/2023 18 29/07/2023 21

31 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

37 एफएफ स्टेशनों पर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

35 निगरानी स्टेशनों पर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और दादरा और नगर हवेली में गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के 40 एफएफ स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा-रेखासे अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 51 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक प्राप्त हुआ ।

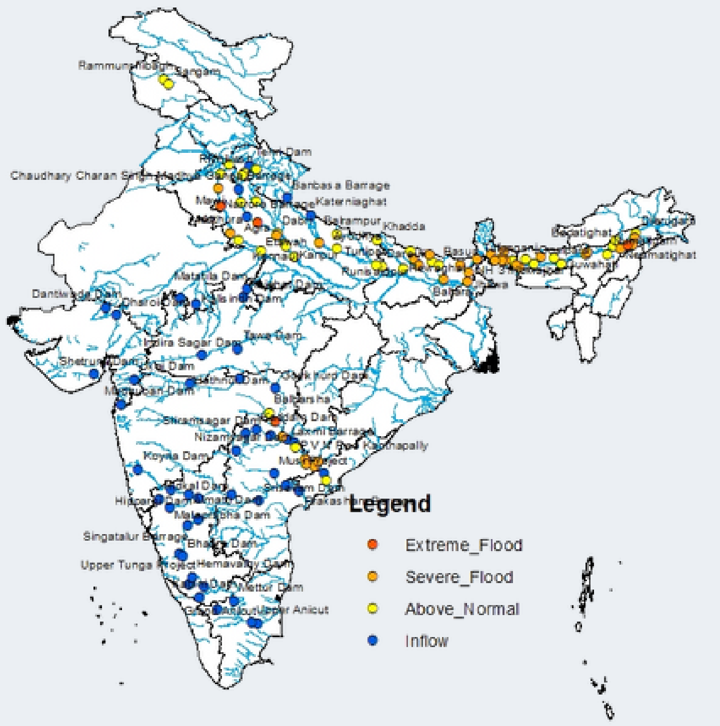

Water Sector-News

- लोगों को कोसी-गंडक के किनारे से सुरक्षित स्थानों से भेजा गया (दैनिक भास्कर, 03.07.2023)
- यमुना प्रदूषण : एनजीटी ने कहा, स्थिति बेहद निराशाजनक (अमर उजाला, 07.07.2023)
- केंद्र की ओर से ड्रॉप 23 प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है कोई आपत्ति, केंद्र से 21 पावर प्रोजेक्ट पर काम की मंजूरी मांगी (हिंदुस्तान, 08.07.2023)
- नेपाल और भारत पंचेश्वर बहू उद्देशीय बिजली सन्यत्र की 'डीपीआर' को देंगे अंतिम रूप (जनसत्ता, 09.07.2023)
- गंगोत्री से लेकर रुड़की तक गंगाजल पीने योग्य (हिंदुस्तान, 12.07.2023)
- यमुना का रौद्र रूप...दिल्ली मे बाढ़ कभी भी, हिमाचल में संकट...20 हज़ार पर्यटक फंसे (दैनिक भास्कर, 13.07.2023)
- ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने चीन बना रहा बांध (हरिभूमि, 20.07.2023)
- बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर : केन्द्रीय जल आयोग (जनसत्ता, 22.07.2023)
- केन-बेतवा लिंक: अगस्त में होंगे दौधन डैम के टेंडर, भूमि अधिग्रहण में तेजी के निर्देश (दैनिक भास्कर, 23.07.2023)
- आदिवासियों ने 100 कुएँ 'रीचार्ज' किए, पीएम बोले-यह उत्साहवर्धक (दैनिक भास्कर, 31.07.2023)

Gallery

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बांध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जल आयोग, एनडीएसए एवं टीएचडीसी ने दिनांक 14.07.2023 को टिहरी, उत्तराखंड में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया।

दिनांक 13.07.2023 को प्रो रीता बहुगुणा जोशी जी की अध्यक्षता में राजभाषा समिति ने बेंगलुरु में दक्षिण पश्चिम नदियाँ उप मण्डल, मंगलोर के साथ निरीक्षण बैठक की।

प्रस्तावित पंचनद सिंचाई परियोजना के लिए सीडब्ल्यूसी और सीएसएमआरएस के अधिकारियों द्वारा कबरई, महोबा में मोटे एग्रीगेट स्थल का संयुक्त दौरा किया गया।

हाइड्रोग्राफिक तकनीक का उपयोग करके जलाशयों के अवसादन सर्वेक्षण पर टीएआरसी की 14वीं बैठक मसौदा अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता, ईएमओ की अध्यक्षता में 20.07.2023 को आयोजित की गई थी।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, माननीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 15.07.2023 को नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल में नर्मदा बेसिन संगठन, सीडब्ल्यूसी भोपाल और सीजीडब्ल्यूबी भोपाल के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार, जिला गोंदिया(महाराष्ट्र) द्वारा दिनांक 12.07.2023 को कार्यस्थल रजेगांव, प्रबोधन मध्य संगठन, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर का दौरा किया गया। दौरे के दौरान गेज मापन, डिस्चार्ज मापन, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला-1 तथा फ़ुल क्लाईमेट स्टेशन इन सभी की जानकारी कार्यस्थल कर्मचारी द्वारा महोदय को प्रदान की गई।

इतिहास- मेजा जलाशय परियोजना

योजना

हाल ही में बेलन नदी पर अधिकतम 34.16 मीटर ऊंचाई का एक मृदा बांध बनाया गया है। बेलन टोंस की एक सहायक नदी है, जो स्वयं गंगा को जल प्रदान करती है। यह परियोजना इलाहाबाद (अब प्रयागराज) और मिर्ज़ापुर जिलों में टोंस-लापरी और करनौती-गंगा दोआब के बीच स्थित पिछड़े और अविकसित क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना चाहती है, जो अब तक सिंचाई के किसी भी भरोसेमंद स्रोत से वंचित था। यद्यपि यह क्षेत्र अच्छी फसल पैदा करने में सक्षम है, फिर भी अतीत में कभी-कभी सूखे और अकाल का शिकार होता रहा है। यह परियोजना इस क्षेत्र में समृद्धि लाने में काफी मदद करेगी। इसके अलावा यह मछली पालन के लिए भी प्रावधान करेगा।

मेजा जलाशय परियोजना में बेलन नदी पर 34.16 ऊंचा और 2.4 किमी लंबा मुख्य बांध और टोंस-लापरी और करनौती-गंगा दोआब के सूखे इलाकों को सिंचाई प्रदान करने के लिए 326.6 किमी नहरों का एक नेटवर्क शामिल है, जिसमें क्रमशः 24686 हेक्टेयर और 30270 हेक्टेयर का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है।

बांध के निर्माण के लिए जांच 1955 में ही की गई थी। 1956 में, एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और बेलन नदी पर धुरिया में बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। बाद में, विस्तृत भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण करने के बाद, यह पाया गया कि बांध स्थल से एक भ्रंश क्षेत्र गुजरता है जो निर्माण में खतरे और कठिनाइयां पैदा कर सकता है और बांध की लागत में वृद्धि कर सकता है।

इसके बाद लगभग सात स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। सभी तकनीकी पहलुओं और इसमें शामिल लागत पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि सभी सात स्थलों में से सबसे अच्छा महादेव गांव के पास का स्थल है, जो बखर नदी के संगम से लगभग 6.4 किमी नीचे है। तीसरी योजना अवधि के दौरान निर्माण कार्य गंभीरता से लिया गया।

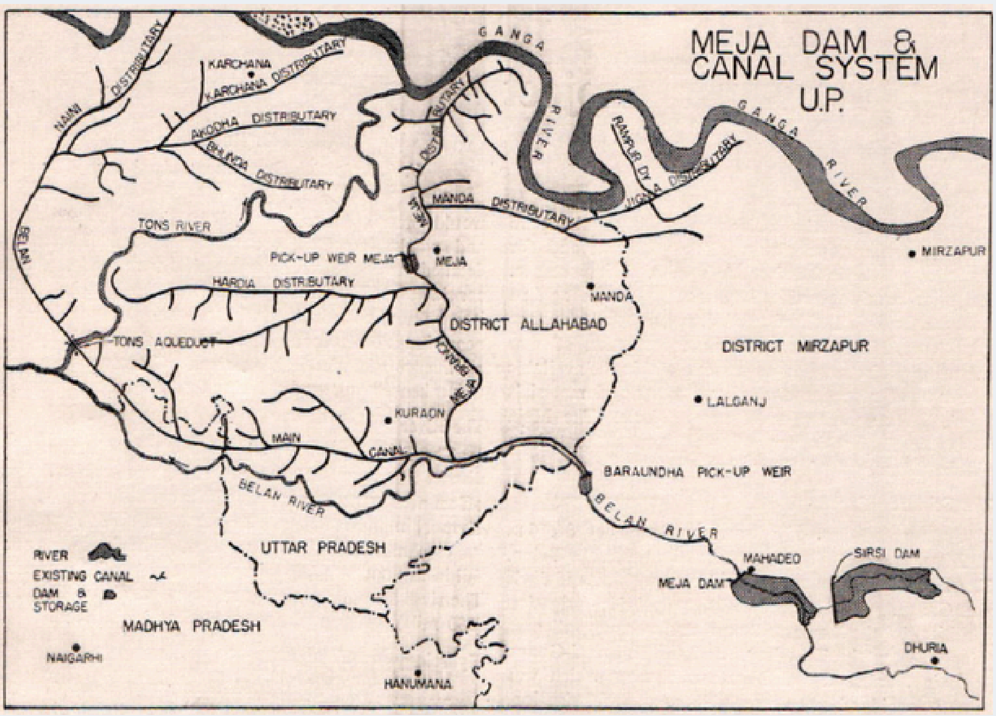

नदी

बेलन नदी का उद्गम जनपद मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज के पास से होता है। यह अपनी सहायक नदियों के साथ बांध स्थल तक पहुंचने से पहले किमोर रेंज के उत्तर में 2020 वर्ग किमी के क्षेत्र में बहती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का एक हिस्सा पहाड़ी और जंगली है। इलाके की प्रकृति के कारण नदी में बाढ़ तेजी से बढ़ती और घटती है। मेजा बांध पर रुकने से पहले नदी लगभग 240 किमी तक टेढ़ी-मेढ़ी गति से बहती है।

मुख्य बांध

पूरे बांध का निर्माण समरूप मिट्टी के खंड में किया गया है, जिसमें नीचे की ओर चट्टान और बांध के ऊपरी हिस्से पर पत्थर की पिचिंग है। नदी के हिस्से में बांध की अधिकतम ऊंचाई 34-16 मीटर है, जिसमें ऊपर की ओर ढलान 3-5:1 और नीचे की ओर ढलान 3-25:1 है, चट्टान के शीर्ष पर 4-57 मीटर की ऊंचाई और चट्टान के किनारे पर 2:1 की पार्श्व ढलान है।

नींव में उचित बंधन और कटाव सुनिश्चित करने के लिए लगभग 3.05 मीटर गहरी एक कोर खाई प्रदान की गई है। इससे बांध से रिसाव न्यूनतम हो गया। नींव में दरारों के माध्यम से रिसाव के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, कुछ हिस्सों में, जहां बांध की ऊंचाई 22.87 मीटर या उससे अधिक थी, रॉक कर्टेन ग्राउटिंग प्रदान की गई थी, ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके। नदी के ऊपरी हिस्से में पानी की गहराई से 10 गुना अधिक लंबाई तक मिट्टी का एक आवरण बिछाया गया था, जिसकी मोटाई 1.52 से 3.05 मीटर के बीच थी, जहां प्राकृतिक मिट्टी का आवरण गायब था।

स्पिलवे और नहर स्लुइस

अधिकतम बाढ़ निर्वहन 7924 घन मीटर प्रति सेकंड होने का अनुमान लगाया गया था। प्रति सेकंड 5943 घन मीटर के डिस्चार्ज को पारित करने के लिए 12.2 मीटर x 6.1 मीटर के 13 गेटों के साथ दाहिने किनारे पर एक गेटेड स्पिलवे प्रदान किया गया था। स्पिलवे की निरंतरता में दाहिनी ओर का विच्छेदी खंड, प्रति सेकंड 1698 घन मीटर की देखभाल करता है। जबकि शेष 283 घन मीटर प्रति सेकंड 2.14 मीटर के मुक्तांतर के विरुद्ध 0.915 मीटर के बाढ़ उत्थापक के द्वारा जलाशय में समा जाता है।

दरार वाले हिस्से का शीर्ष उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.610 मीटर ऊंचा रखा गया था। यह विच्छेदी खंड केवल आपातकालीन स्थिति में काम करता है और जैसे ही जलाशय में पानी का स्तर उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह टूट जाता है।

अतिवाही के नीचे की ओर जमीन में काफी ढलान थी जिसके कारण पानी अतिवाही के बायीं ओर बहता था। पानी के इस प्रवाह को रोका गया और बांध के सिरे तक पहुंचने और उसे क्षतिग्रस्त होने से बचाया गया। इसलिए पत्थर की चिनाई के साथ 173.80 मीटर लंबा एक गाइड बांध का निर्माण किया गया था। स्पिलवे से गुजरने वाले पानी की तेज धाराओं से गाइड बांध की रक्षा के लिए बांध के निकास भाग को तार के बक्सों में पत्थर रखकर भरा गया था। सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की में स्पिलवे के डिज़ाइन का मॉडलों पर सतही प्रवाह स्थितियों के लिए परीक्षण किया गया था। संस्थान की सिफ़ारिशों पर, मुख्य स्पिलवे शिखर से लगभग 228.75 मीटर नीचे की ओर एक सहायक निम्न शिखर बांध बनाया गया था।

पानी छोड़ने के लिए नहर स्लुइस स्पिलवे और नदी के बीच दाहिने किनारे पर स्थित थीं। स्लुइस में 1.52m x 3.05m के दो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट वाहिका होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में चिनाई वाले युग्म कूप होते हैं, एक प्रचालन फाटक के लिए और दूसरा आपातकालीन फाटक के लिए। स्लुइस के नीचे चैनल की चौड़ाई 4.88 मीटर है और पानी की गहराई 3.26 मीटर है जो 56.6 घन मीटर प्रति सेकंड की डिस्चार्ज क्षमता प्रदान करती है। सिंचाई की मांग के समय, पानी को स्लुइस के माध्यम से छोड़ा जाता है। यह नदी में बहता है और बरौंधा वियर में इकट्ठा होता है और बेलन नहर के माध्यम से वितरित होता है जो बरौंधा पिक-अप वियर से निकलती है।

निर्माण प्रगति

वर्तमान बांध स्थल का चयन अंततः वर्ष 1961 में किया गया। बांध पर काम मैन्युअल श्रम द्वारा शुरू किया गया था। काम के लिए ऑर्डर किए गए 13 में से सात मोटर चालित स्क्रेपर जनवरी 1963 में आ गए जब मिट्टी का काम पूरे जोरों पर शुरू हो गया था। शेष स्क्रेपर्स 1964 में प्राप्त हुए थे। नदी के अंतराल को छोड़कर सभी मिट्टी का काम जुलाई 1965 तक पूरा हो गया था। नहर स्लुइस-कम-डायवर्जन चैनल का निर्माण अप्रैल 1965 तक पूरा हो गया था। सड़क पुल को छोड़कर स्पिलवे भी जुलाई 1965 तक काफी हद तक पूरा हो गया था। नदी के अंतराल को बंद करना एक प्रमुख ऑपरेशन था, जिसमें 915 मीटर तक की लीड के साथ 84900 घन मीटर से अधिक मिट्टी के काम के निष्पादन की आवश्यकता थी। और इसमें 56.6 घन मीटर प्रति सेकंड की शीतकालीन बाढ़ डायवर्जन क्षमता प्रदान करने के लिए 16.47 मीटर ऊंचे कॉफ़र बांध का निर्माण शामिल था और साथ ही मौजूदा नहरों को चलाने के लिए 14.15 घन मीटर प्रति सेकंड निरंतर निर्वहन प्रदान करना शामिल था।

कॉफ़र बांध का निर्माण अपने आप में एक अद्भुत कार्य था। नदी के तल को साफ करना, आवरण बिछाना, चट्टानों में बड़ी मात्रा में श्रेणीबद्ध सामग्री बिछाना और नदी के पीछे के पानी को रोकने के लिए नीचे की ओर एक रिंग बांध बनाना सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना था। मई 1966 के मध्य तक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संपूर्ण मिट्टी का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और ऊपरी सतह पर पत्थर लगाने का काम जुलाई 1966 तक पूरा कर लिया गया। कार्यक्रम के अनुसार उसी वर्ष मानसून के दौरान जलाशय भरना शुरू हो गया।

नहरों के निर्माण का कार्य भी साथ-साथ किया गया। लगभग 313.75 किमी नहरें पहले ही खोदी जा चुकी हैं और सिंचाई के लिए चल रही हैं। जो चैनल जल्दी पूरे हो गए थे, उन्हें मौजूदा सिरसी जलाशय और बेलन नदी के प्रवाह से पानी दिया गया था। विचार यह था कि सिंचाई के विकास के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाए और मेजा जलाशय क्षमता के उपयोग में समय के अंतराल को कम किया जाए।

1966 में पहली बार भरने पर बांध 19.22 मीटर की गहराई तक भर गया था और 1966 के सूखे में सिंचाई के लिए लगभग पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। 1967 के मानसून ने इसे फिर से केवल 25.93 मीटर की गहराई तक भर दिया, अतिरिक्त प्रवाह को चार से पांच वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे जलाशय को उसके पूर्ण स्तर तक भरने की दृष्टि से बाहर निकलने दिया गया।

मेजा जलाशय और सिरसी जलाशय एक सिंचाई ग्रिड बनाते हैं और बेलन नहर प्रणाली के माध्यम से क्षेत्र को पोषित देते हैं।

लाभ

इस योजना द्वारा लाभान्वित होने वाला कुल कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 54320 हेक्टेयर है। परियोजना में प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई 326 किमी चैनलों के नेटवर्क के माध्यम से 25947 हेक्टेयर है, जो प्रति मील 128 हेक्टेयर और खेती योग्य कमांड क्षेत्र पर 48 प्रतिशत की तीव्रता देती है।

(स्रोत: भागीरथ जनवरी 1968)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल
- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनील कुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

No. CWC/2024/121 | cwc.gov.in | /CWCOfficial.GoI | /CWCOfficial.GoI | /CWCOfficial_GoI | c/CWCOfficialGoI